

190 डिप्टी कलेक्टरों को मिली पदोन्नति की सौगात

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 7 जुलाई. लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 190 तहसीलदारों, अधीक्षक भू अभिलेख और प्रभारी डिप्टी कलेक्टर को आखिरकार पदोन्नति की सौगात मिल गई है. उन्हें अब राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत किया गया है.

यानी ये सभी अब डिप्टी कलेक्टर कहे जाएंगे. अब प्रभारी का टैग उनके पदनाम से हट जाएगा. ये टैग का बोझ वे पिछले



10 वर्ष से दो रहे थे. मप्र लोक सेवा आयोग ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए इन अधिकारियों की अनुशंसा की थी, एमपीपीएससी से संबंधित दावेदारों की सूची मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बिना

देरी किए आदेश जारी कर दिए. यहां बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह ही इस संबंध में आदेश जारी किए थे, कि विभाग अपने स्तर पर विभागों में तबादले कर सकते हैं, ये तबादले कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे, उसके बाद सबसे पहले विधानसभा सचिवालय ने अपने अधिकारियों- कर्मचारियों को पदोन्नत करने के आदेश जारी किए. फिर मंत्रालय संवर्ग में कर्मचारियों के प्रमोशन किए गए. अब ये सिलसिला दूसरे विभागों में भी शुरू हो गया है.

एक नजर में फर्जी पोस्टर के मामले में एफआईआर की मांग

भोपाल. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कथित रूप से एआई (ऑटोफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से तैयार किए गए फर्जी सोशल मीडिया पोस्टर के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. इस संबंध में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साई मनोहर को ज्ञापन सौंपा. मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कुंदन नाजबी, अनीशी बुंदेला, रोशनी यादव सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल थे.

अश्लील हरकत के मामले में कार्रवाई

देवास. शहर स्थित मल्हार स्मृति पार्क में सार्वजनिक स्थान पर कथित अश्लील हरकत करने के वायरल वीडियो के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 एफ 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में शाहरुख अब्बासी शामिल है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है तथा प्रकरण में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

स्मार्ट मीटर का विरोध, युवा कांग्रेस ने किया घेराव

विशेष संवाददाता
भोपाल, 7 जुलाई. अघोषित बिजली कटौती, मनमाने बिजली बिलों और कथित रूप से जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस ने रातीबड़ स्थित बिजली कार्यालय का घेराव किया.

भोपाल ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष प्रिस सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नागरिकों और किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी पूर्व सूचना के कई-कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे आमजन



और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ज्ञापन में अघोषित बिजली कटौती और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई.

भरोसा करने से बचें ...

हां यह सच हैं कि साइबर ठग अब बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल तकनीकी सहायता और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जैसी रोजमर्रा की सुविधाओं का सहारा लेकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं. ऐसे मामलों में किसी भी अनजान व्यक्ति से बैंकिंग जानकारी साझा करने और इंटरनेट पर मिले संदिग्ध हेल्पलाइन नंबरों पर भरोसा करने से बचना चाहिए.

एडीसीपी क्राईम, राजेश दंडोतिया

सामने आए हैं. लसुंडिया थाना क्षेत्र में कैलोद हाला नावासी अखिलचंद्र गायकवाड़ ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन कार्ड के लिए आवेदन किया था. कुछ दिन बाद खुद को बैंक अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति ने फोन कर खाते से जुड़ी

जानकारी ले ली. इसके बाद उनके खाते से करीब सवा लाख रुपए निकाल लिए. एक अन्य मामले में स्कीम नंबर 78 निवासी गोपाल वाकोडे ने बताया कि 17 जून को उनका मोबाइल हैक हो गया, थोड़ी देर बाद खाते से रकम निकलने के लगातार मैसेज आने लगे. जांच में सामने आया कि



पहुंचकर नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक कर रही है. लोगों को संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करने, ऑनलाइन लेदेन में सतर्कता बरतने तथा साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन

1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है. मोबाइल बरामदगी के लिए पुलिस से सीईआईआर (सेंट्रल इन्विजमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल, तकनीकी विश्लेषण और जिला साइबर टीमों की समन्वित कार्रवाई का सहारा लिया.

स्मार्ट सिटी के 3 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस

ग्वालियर, 7 जुलाई. कलेक्टर रुचिका चौहान ने सचिन तेंदुलकर मार्ग उन्नयन कार्य निर्माण की सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उपयोग की जाने वाली समग्री का स्रोत अनुमोदन करने, कार्य का तकनीकी परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के साथ ही अनुबंधीय प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन की निगरानी करने संबंधी दायित्वों का निर्वहन न करने पर स्मार्ट सिटी के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्मार्ट सिटी के तीनों इंजीनियरों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि सचिन तेंदुलकर मार्ग उन्नयन कार्य में लापरवाही पाए जाने

पर क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए. तीनों अधिकारियों को पांच दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जवाब समाधानकारक न पाए जाने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी. कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के कार्यपालन यंत्री अंकित शर्मा, सहायक यंत्री अनिल चौहान एवं उप यंत्री अभिषेक त्रिपाठी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है. उन्होंने कारण बताओ सूचना पत्र में स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त मेन हॉल कवर का नियमानुसार स्रोत अनुमोदन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सुनिश्चित नहीं किया गया.

सिंधार ने जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने मंगलवार को राज्य सरकार पर किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रोष्पकालीन मूंग उत्पादक किसानों की पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जानी चाहिए. उनका आरोप था कि सरकार द्वारा निर्धारित खरीदी लक्ष्य वास्तविक उत्पादन की तुलना में काफी कम है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और इसका लाभ बीचौलियों को मिल रहा है.

लक्ष्य और केंद्रों की संख्या बढ़ाने, पंजीयन एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा प्राभावित जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर किसानों से संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने की मांग की.



एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 भोपाल में 13 डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर पर फोकस

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 7 जुलाई. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 13 जुलाई को भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 : जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर एडिशन का आयोजन किया जाएगा.

इसका उद्देश्य उच्च-विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को गति देना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर क्षेत्र में प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है.



कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को साझा करेंगे और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर निवेश, परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं भावी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 8 जुलाई को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि-पूजन करेंगे वीन की अग्रणी बहुरीय निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी गुआंशी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार मप्र को निर्माण उपकरण विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए है. पाँथमपुर में स्थापित होने वाला नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा.

जनसुविधा के विस्तार से विकास को नई गति : ऊर्जा मंत्री तोमर

ग्वालियर, 7 जुलाई. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगलवार को ग्वालियर उपनगर में विभिन्न 1.86 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली विभिन्न विकास योजनाओं का भूमिपूजन किया. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षद गण बड़ी संख्या में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, विद्युत वितरण कंपनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्वालियर बदल रहा है और निरंतर विकास के पथ पर चल रहा है. इस विकास और समृद्ध होने ग्वालियर की प्रगति यात्रा को निरंतरता देने के लिए ग्वालियर को एक बार औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल की जा रही है, ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के लिए शहर के बाहर न जाना पड़े.



31 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

6 दिन की बारिश से सामान्य वर्षा के करीब पहुंचा प्रदेश

भोपाल, 7 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और जुलाई की शुरुआत से हो रही लगातार बारिश ने प्रदेश में वर्षा की कमी लगभग पूरी कर दी है. मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में रूक-रूक बारिश लगातार हो रही है.

पिछले छह दिनों में हुई झमाझम बारिश के बाद राज्य में औसत वर्षा करीब 7 इंच दर्ज की गई है, जो सामान्य से केवल एक प्रतिशत कम है. मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 31 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर जिलों में अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अर्रंज अलर्ट जारी

किया गया है. वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, मैहर, दमोह, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतुल, सीहोर, हरदा, आगर-मालवा, राजगढ़, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

प्रदेश में सबसे अधिक असर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में देखने को मिल रहा है. इन क्षेत्रों के अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. देवास इस सीजन का सबसे अधिक बारिश वाला जिला बन गया है, जहां अब तक 15.3 इंच वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है. लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ा है, जबकि कई स्थानों पर निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है.

बारिश के कारण प्रदेशभर में तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. मलाजखंड सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन सहित प्रमुख शहरों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. जून में वर्षा सामान्य से कम रही थी, लेकिन जुलाई में मानसून की सक्रियता बढ़ने से बारिश का आढ़ाड़ा तेजी से सामान्य स्तर के करीब पहुंच गया है.

पेज एक का शेष अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट ...

स्थानों पर लगाया गया था. इसके अलावा सूरत से कई जिंदा बम भी बरामद किए गए थे, जो तकनीकी कारणों से विस्फोट नहीं कर सके थे. जांच एजेंसियों के अनुसार, हमलों में भीड़भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक रस्सों और स्थिति अस्थिरता सहित कई स्थानों को निशाना बनाया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि इन धमाकों की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) से जुड़े आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) ने ली थी. जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में दावा किया था कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के प्रतिशोध की शंका से इस हमले की साजिश रची गई थी. इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत में हुई थी.

फरवरी 2022 में अदालत ने 77 आरोपियों में से 28 को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था, जबकि 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया. इनमें 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. भारतीय न्यायिक इतिहास में एक साथ इतने अधिक दोषियों को मृत्युदंड सुनाए जाने का यह प्रमुख मामलों में से एक माना गया. अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले की जांच गुजरात पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने की थी. जांच दल में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र प्रस्तुत किया था.

मांग जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

किसानों के हित में तत्काल हस्तक्षेप करे सरकार

विशेष संवाददाता
भोपाल, 7 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर शत-प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है.

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो लाखों उत्पादक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. जीतू पटवारी ने अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश देश का अग्रणी



दलहन उत्पादक राज्य है. किसानों ने सरकार के उत्पादन बढ़ाने के आह्वान पर भारी निवेश कर रिकॉर्ड स्तर पर मूंग का उत्पादन किया, लेकिन अब उन्हें एमएसपी पर अपनी उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि

वास्तविक उत्पादन की तुलना में खरीदी का लक्ष्य काफी कम निर्धारित किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ सकती है. उन्होंने हरदा सहित कई जिलों में किसानों के विरोध-प्रदर्शन का भी उल्लेख किया.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पंजीयन, स्लॉट आवंटन, खरीदी क्षमता, गुणवत्ता परीक्षण और भुगतान व्यवस्था में भी खामियों का आरोप लगाया. उन्होंने सभी पंजीकृत किसानों से शत-प्रतिशत एमएसपी पर खरीदी, खरीदी

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने मंगलवार को राज्य सरकार पर किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रोष्पकालीन मूंग उत्पादक किसानों की पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जानी चाहिए. उनका आरोप था कि सरकार द्वारा निर्धारित खरीदी लक्ष्य वास्तविक उत्पादन की तुलना में काफी कम है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और इसका लाभ बीचौलियों को मिल रहा है.

भाजपा पार्षदों ने सौंपा कलेक्टर मीणा को ज्ञापन

दुकान आवंटन प्रक्रिया निरस्त करने की मांग

धार, 07 जुलाई . धार नगर पालिका द्वारा शहर के तीन स्थानों पर निर्मित दुकानों की आवंटन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और एल्डरमैन के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को ज्ञापन सौंपकर निविदा प्रक्रिया निरस्त करने और नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग की.

विधायक प्रतिनिधि शिव पटेल ने बताया कि लालबाग मार्केट,

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और बालाजी हनुमान मंदिर के समीप निर्मित दुकानों के विक्रय की प्रक्रिया अपारदर्शी और मनमाने ढंग से संचालित किए जाने का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत प्रस्तुत की गई है. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ई-ऑक्शन के माध्यम से जारी की गई निविदा की सूचना परिषद के पार्षदों, शासन द्वारा नियुक्त एल्डरमैन तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को विधिवत नहीं दी गई. साथ ही आरक्षण प्रक्रिया में भी जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया.